"कन्सर्न ओवर पब्लिक सैक्टर फैलियर" शीर्षक वाला समाचार

2020. **श्री सुब्रह्मण्यम स्वामी :** क्या कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 29 मार्च, 1988 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में "कन्सर्न ओवर पब्लिक सैक्टर फेलियर" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि 1985 में रतन टाटा की अध्यक्षता में गठित उच्च अधिकार प्राप्त समिति ने सरकारी क्षेत्र में चलायी जा रही परियोजनाओं की प्रगति के प्रति असंतोष व्यक्त किया है ;

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है और उसका क्या परिणाम रहा ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बीरेन सिंह इंगती) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) श्री रतन एन० टाटा की अध्यक्षता में गठित परियोजना कार्यान्वयन सलाहकार परिषद् ने अपनी रिपोर्ट में (क) परियोजना कार्यान्वयन प्रणाली में सुधार और (ख) संगठनात्मक विकास का उल्लेख किया है, जिसकी फिलहाल, सरकार के विभिन्न स्तरों पर जांच की जा रही है, इस स्तर पर विषय वस्तु को बताना जन हित में नहीं होगा।

नाभिकीय विद्युत केन्द्रों की स्थापना

2021. **श्री सुब्रह्मण्यम स्वामी :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नाभिकीय विद्युत निगम द्वारा देश में और अधिक विद्युत उत्पादन केन्द्र स्थापित करने के लिए कतिपय प्रस्ताव सरकार की स्वीकृति हेतु भेजे गए हैं ;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या सरकार द्वारा इन सभी प्रस्तावों की स्वीकृति दिए जाने की संभावना है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रानिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) और (ख) न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन की स्थापना हाल ही में हुई है। तथापि, सरकार ने सिद्धांत रूप से यह लक्ष्य अनुमोदित कर दिया है कि सन् 2000 तक 10,000 मेगावाट परमाणु बिजली पैदा करने की क्षमता वाले बिजलीघर लगा दिए जाएं, जिनमें 235 मेगावाट और 500 मेगावाट क्षमता के दाबित भारी पानी रिएक्टर शामिल होंगे।

(ग) परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थल चयन समिति ने देश के सभी क्षेत्रों में स्थित स्थलों का अध्ययन परमाणु बिजलीघर लगाने की दृष्टि से किया है। समिति की रिपोर्ट सरकार के विचाराधीन है।

"प्लानर्स ब्लेम्ड फार शार्टेज" शीर्षक के अधीन प्रकाशित समाचार

2022. **श्री रशीद मसूद :**
श्री सुब्रह्मण्यम स्वामी :

क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 26 अप्रैल, 1988 के इकानामिक टाइम्स में "प्लानर्स ब्लेम्ड फार शार्टेज" शीर्षक के अधीन प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;